जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा

कोविड के कारण अधिकारी अलग रणनीति अपनाकर कार्य करें अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, 12 मई। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्री सुधांश पंत ने प्रदेश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों के बीच जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हर घर नल कनैक्शन के कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों को अलग रणनीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बदली स्थितियों के सामान्य होने तक अधिकारी कार्यालयों के स्तर पर तकनीकी स्वीकृतियां एवं निविदा जारी करने जैसे कई कार्य सम्पादित कर इस समय का अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं। बाद में हालात सामान्य होने पर अन्य कार्यों को गति दी जा सकती हैं।

श्री पंत बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृति कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जेजेएम की प्रगति में कमी दर्ज की गई है, मगर सभी रीजन और जिला कार्यालयों के स्तर पर ऐसे योजनाबद्ध प्रयासों से प्रदेश द्वारा वार्षिक कार्य योजना में लक्षित कार्यों को पूरा किया जा सकता है।

एसीएस ने निर्देश दिए कि हर घर नल कनैक्शन देने के कार्य को लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने के लिए तकनीकी स्वीकृतियां, निविदा जारी करने के बाद वर्क ऑर्डर जारी करने के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि धरातल पर हर घर नल कनैक्शन देने का वास्तविक कार्य गति पकड़ सके। उन्होंने जिलों में आईएसए (इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज) को सक्रिय करते हुए आगामी दिनों में उनके माध्यम से 'विलेज एक्शन प्लान' तैयार करने के कार्य को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

श्री पंत ने वीसी में जेजेएम के कार्यों की रीजन, सर्किल और जिला स्तर पर प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की। इसमें पाया गया कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

(एसएलएससी) की गत बैठकों में मेजर प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त स्वीकृत 9101 गांवों में से अब तक 5032 गांवों की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां तथा 3128 गांवों के कार्यों की निविदाएं जारी की गई है। एसएलएससी की स्वीकृतियों की तुलना में चुरू जिले में सभी तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। बूंदी में 98 प्रतिशत, भीलवाड़ा व नागौर में 96-96 प्रतिशत तथा बारां में 94 प्रतिशत तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। इसकी तुलना में जैसलमेर में 94 प्रतिशत, श्रीगंगानगर में 79 प्रतिशत, करौली में 72 प्रतिशत, अजमेर में 71 प्रतिशत और बाड़मेर में 69 प्रतिशत तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने का कार्य शेष है। तकनीकी स्वीकृतियों के बाद निविदा जारी करने के मामले में बूंदी 98 प्रतिशत, चुरू 88 प्रतिशत, भीलवाड़ा 80 प्रतिशत, सीकर 75 प्रतिशत तथा जयपुर 73 प्रतिशत निविदाएं जारी कर शीर्ष 5 जिलों में शामिल है, जबकि सबसे कम प्रगति वाले जिलो में जैसलमेर में 96 प्रतिशत, डूंगरपुर में 95 प्रतिशत, पाली में 93 प्रतिशत, अजमेर में 87 प्रतिशत तथा श्री गंगानगर में 86 प्रतिशत निविदाओं का काम बाकी है। एसीएस ने अधिकारियों को एसएसएससी की स्वीकृतियों की तुलना में पिछड़ रहे जिले के अधिकारियों को शेष कार्यों में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए 'पेंडींग टास्क' को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को आगामी एसएलएससी की बैठक के लिए भी सभी जिलों से नए हर घर नल कनैक्शन कार्यों के प्रस्ताव अगले सोमवार तक भिजवाने के निर्देश दिए।

वीसी से जलदाय विभाग की विषिष्ट सचिव श्रीमती उर्मिला राजोरिया, मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) श्री सीएम चौहान, मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट्स) श्री दिलीप गौड़, मुख्य अभियंता (जोधपुर) श्री नीरज माथुर तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ग्रामीण) श्री महेश जांगिड के अलावा प्रदेश भर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों भी जुड़े।

जयपुर जिलें में कोविड की स्थिति की समीक्षा

आईएलआई मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे की गति बढाएं

एसीएस एवं जयपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री पंत ने निजी अस्पतालों का आक्सीजन आडिट कराने के भी दिए निर्देश

जयपुर, 12 मई। जयपुर जिले के प्रभारी सचिव तथा जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने जयपुर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आइएलआई के लक्षणों अथवा कोविड संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए जारी 'डोर टू डोर सर्वे' की गति बढ़ाने एवं हर चरण की समाप्ति पर पुनः लगातार सर्वे जारी रखने के निर्देश दिए हैं। श्री पंत ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर जिले में कोरोना पर नियंत्रण, संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए सामान्य, आईसीयू, वेंटीलेटर बैड, आक्सीजन की उपलब्धता, अस्पतालों की व्यवस्थाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए यह निर्देश प्रदान किए।

श्री पंत ने जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जितनी जल्द कोरोना संभावित अथवा आईएलआई मरीजों का पता लगाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित कोविड कन्सल्टेशन एवं केयर सेंटर से उपचारित कराया जाएगा, इस महामारी पर नियंत्रण की दिशा में उतनी ही तेजी से अग्रसर हूआ जा सकेगा। श्री पंत ने कहा कि मेडिकल किट एवं संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, इस समय संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सर्वे को तेज किया जाना बेहद जरूरी है। जिला कलक्टर श्री नेहरा ने प्रभारी सचिव को 'डोर टू डोर सर्वे' में आईएलआई एवं कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर एसिम्पटोमैटिक, आईएलआई वाले व्यक्ति को एएनएम द्वारा मेडिकल किट देकर प्रारम्भिक उपचार प्रारम्भ कराया जा रहा है और आइसोलेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। हर ब्लाक पर स्थापित कोविड कन्सल्टेशन एवं केयर सेंटर तथा क्षेत्र की सीएचसी पर भी मेडिकल किट की दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं।

हर सेंटर पर आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति कोविड टेस्टिंग के लिए सेंम्पल देने आता है, उसे भी मेडिकल किट दिया जा रहा है।

एसीएस श्री पंत ने जिले में कोविड सैम्पलिंग की संख्या बढाने के लिए भी निर्देशित किया। जिले के प्रभारी सचिव ने जयपुर शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग श्रेणी जैसे सामान्य, आईसीयू, आईसीयू विद वैंटीलेटर में भर्ती कोविड मरीजों की संख्या के अनुसार उनकी वास्तविक आक्सीजन आवश्यकता एवं चिकित्सालयों द्वारा मांग एवं उपभोग बताई जा रही आक्सीजन की मात्रा का आडिट करवाने के भी निर्देश दिए। श्री पंत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हर जरूरतमंद व्यक्ति को इससे आक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री रवि जैन ने आक्सीजन की आदिनांक उपलब्धता की विस्तृत जानकारी दी। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री गौरव गोयल ने वर्तमान में जयपुर में कोविड मरीजों के उपचार के लिए विभिन्न निजी एवं राजकीय अस्पतालों में सभी श्रेणियों के बैड्स की उपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने अब तक आरएमएससीएल, सीएसआर, दानदाताओं एवं अन्य साधनों से उपलब्ध आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की स्थिति की भी जानकारी दी।

———————